बजट में पहली बार खेल उत्पाद के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया, खेल सामान सस्ते होने की उम्मीद, बढ़ेगा व्यापार

खेल उद्योग पर बरसा धन, उड़ान भरेगी मेरठ की इंडस्ट्री

चमकेगा उद्योग

■ सलीम अहमद

मेरठ। दुनिया में खेल उत्पादों के बूते पहचान बनाने वाली स्पोर्ट्स नगरी मेरठ पर आम बजट में पहली बार पैसा बरसा। खेल सामान के लिए 500 करोड़ के प्रावधान और खेलो इंडिया मिशन मेरठ के खेल उत्पादों के निर्माण, निर्यात और स्थानीय बाजार में बिक्री को बढ़ावा देगा। खेल उद्योग के विकास और निर्यात-कारोबार को पंख लगने की उम्मीद जगी है।

खेल उद्यमियों की कुछ मांगें भले ही अधूरी रह गईं, लेकिन सरकार ने पहली बार आम बजट में खेल उद्योग के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल चेयरमैन सुमनेश अग्रवाल का कहना है इसका सीधे मेरठ के खेल उद्योग को लाभ मिलेगा। अगले दशक में खेलों में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू होगा। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के अलावा खेल तकनीक को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। प्रशिक्षण और खेल इन्फ्रा को विकसित करने पर जोर रहेगा। मेरठ के साथ जालंधर खेल उद्योग को लाभ मिलना तय है।

किफायती और गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्री पर जोर

उद्यमी कहते हैं कि किफायती और गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्री पर जोर दिया है। इस पहल का उद्देश्य भारत को उच्च गुणवत्ता वाले, किफायती टिकाऊ खेल उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनाना है। खेल सामग्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थ पहल (समर्थ इनिशिएटिव) का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें विनिर्माण और खिलाड़ियों के लिए बेहतर संसाधनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है सीमा शुल्क में संभावित संशोधन के कारण आयातित उच्च-स्तरीय खेल सामग्री महंगी हो सकती हैं। बजट में इन्फ्लेटेबल बॉल, हॉकी स्टिक, क्रिकेट गियर और सुरक्षा उपकरण जैसी वस्तुओं के लिए घरेलू उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

पहली बार इसलिए प्राथमिकता में आया

2030 में राष्ट्र मंडल एवं 2036 में ओलंपिक खेलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं इन खेलों में शत प्रतिशत देश में उत्पादित खेल उपकरण ही प्रयोग हों। इसके लिए नीति आयोग और युवा एवं खेल मंत्रालय कवायद में जुटा है। मेरठ-जालंधर के खेल उद्योग पर फोकस किया हुआ है। कई दौर की बैठकें, खेल उद्यमियों के साथ वार्ता हो चुकी है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में खेल उद्योग की हिस्सेदारी 30 फीसदी बढ़े।

1500 से 2000 करोड़ करीब मेरठ के खेल उद्योग

700 करोड़ से अधिक करीब मेरठ से खेल सामानों का निर्यात

1100 करोड़ से अधिक करने का निर्यात का लक्ष्य

मेरठ की खेल उद्योग में स्थिति

जालंधर के बाद मेरठ भारत में खेल सामान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह देश के कुल खेल निर्यात में 40 फीसदी का योगदान देता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत मेरठ के खेल सामान को प्रदेश सरकार ने चयनित किया हुआ है। यहां की 35,000 से अधिक इकाइयां क्रिकेट बैट, इन्फ्लेटेबल बॉल्स और फिटनेस उपकरण बनाती हैं, जो दुनियाभर में 100 से अधिक देशों को निर्यात होते हैं।

यह निकलेगा परिणाम

खेल उद्यमियों का मानना है 500 करोड़ बजट से खेल उद्योगों का विकास होगा। खेल उपकरण सस्ते होंगे और कारोबार-व्यापार बढ़ेगा। गुणवत्ता बेहतर होगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कहना इनका

बजट में खेल सामग्री उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत और अगले दशक तक इसके विस्तार के अलावा, अन्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अंबर आनंद, वाइस चेयरमैन, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल

बजट में खेल उद्योग के लिए 500 करोड़ का प्रावधान मेरठ खेल उद्योग को विकास के पंख लगाएगा। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर में बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के उन्नयन में खेल सामग्री क्लस्टर भी शामिल हैं।

तरुण मक्कड़, निदेशक एचआरएस

खेल सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने को नई पहल प्रस्तावित की गई है, जिसमें खेल उपकरणों के डिजाइन और सामग्री विज्ञान में अनुसंधान और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरठ के खेल उद्योग का विकास होगा।

– **हर्ष भारद्वाज**, निदेशक, हीरा स्पोर्ट्स गुड्स

जंयत चौधरी ने सांसद चंदन चौहान को भेजा था मेरठ

नीति आयोग के मुख्य सलाहाकार संजीत सिंह मेरठ और जालंधर के खेल उद्यमियों के साथ दस से अधिक बैठकें कर चुके हैं। मेरठ के खेल उद्योग को बढ़ावा देने को केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने पिछले दिनों सांसद बिजनौर चंदन चौहान को मेरठ भेजा था। उन्होंने खेल उद्यमियों से संवाद कर उनकी समस्याएं और खेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव लेकर रिपोर्ट दी थी। खेल एवं युवा मंत्रालय के साथ नीति आयोग के अफसर लगातार मेरठ के खेल उद्योग के विकास के लिए जुटे हैं। कार्ययोजना पर अगले माह से काम शुरू होने की उम्मीद है।